भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1342
जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।
11 श्रावण, 1946 (शक)

टेक-स्टार्टअप को सहायता प्रदान किया जाना

1342. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कुल कितने टेक-स्टार्टअप्स को सरकारी योजनाओं द्वारा सहायता प्रदान की गई है;
(ख) प्रत्येक योजना के अंतर्गत स्टार्टअप्स को कितनी धनराशि संवितरित की गई है;
(ग) सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स की सफलता/असफलता दर क्या है जिनमें प्रमुख संकेतक जैसे कि बढ़े हुए आंकडें, प्राप्त किए गए लक्ष्य या अतिरिक्त निधियन प्राप्त करना शामिल है;
(घ) क्या सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने या ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित स्टार्टअप्स की कोई उल्लेखनीय सफलताओं के किस्से हैं या ऐसे किन्हीं मामलों का अध्ययन करवाया गया है; और
(ङ) टेक स्टार्टअप पारितंत्र को निरंतर सहायता प्रदान करने और उसमें वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए लगातार विभिन्न प्रयास करती रहती है। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) जैसी प्रमुख योजनाएं स्टार्टअप को उनके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं, ताकि स्टार्टअप को एंजल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश जुटाने या वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए एक स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके। परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 2024 तक भारत में 1.43 लाख से अधिक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ('एमईआईटीवाई') द्वारा की गई पहलें इस प्रकार हैं:

i. **प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन और उद्यमियों का विकास (टाइड 2.0) योजना:** एमईआईटीवाई ने 2019 में 5 वर्षों की अवधि में 264.62 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ टाइड 2.0 योजना शुरू की। यह उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आईसीटी स्टार्टअप्स का समर्थन करने में लगे उच्च शिक्षा संस्थानों और

प्रमुख आरएंडडी संगठनों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अब तक 51 टाइड 2.0 इनक्यूबेशन केंद्रों को सहायता दी गई है और उन्हें चालू किया गया है।

ii. **उत्पाद इनोवेशन, विकास और वृद्धि के लिए एमईआईटीवाई का स्टार्टअप एक्सेलेरेटर (समृद्ध) योजना:** समृद्ध योजना को भारत की तकनीकी चुनौतियों को हल करने और इस प्रकार एक सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए संभावित आईटी-आधारित स्टार्ट-अप का चयन करने और उन्हें गति देने के लिए मौजूदा और आने वाले एक्सेलेरेटर का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था। समृद्ध योजना चयनित एक्सेलेरेटर को स्टार्ट-अप्स को एक्सेलेरेटर सेवाएँ प्रदान करने के लिए समर्थन प्रदान करेगी, साथ ही 40 लाख रुपये तक की वन-टू-वन मिलान निधि सहायता भी प्रदान करेगी। समूह के पहले दौर में, 175 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए देश के 14 राज्यों और 12 शहरों में 22 एक्सेलेरेटर चुने गए हैं। इन एक्सेलेरेटर में सरकार समर्थित संगठन, शैक्षणिक संस्थान, कॉर्पोरेट एक्सेलेरेटर और निवेश फर्म शामिल हैं।

iii. **नेक्स्ट जनरेशन इनक्यूबेशन स्कीम (एनजीआईएस):** एनजीआईएस को सॉफ्टवेयर उत्पाद इकोसिस्टम का समर्थन करने और सॉफ्टवेयर उत्पाद पर राष्ट्रीय नीति (एनपीएसपी) 2019 के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संबोधित करने के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना को 12 स्थानों यानी अगरतला, भिलाई, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ और प्रयागराज , मोहाली/चंडीगढ़, पटना और विजयवाड़ा से लॉन्च करने का प्रस्ताव है । इस योजना में समाधान उन्मुख वास्तुकला है और इसका लक्ष्य 95.03 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ 3 साल की अवधि में टियर-2/3 शहरों में 300 टेक स्टार्ट-अप को सहायता प्रदान करना है।

iv. **डोमेन विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र (सीओई):** एमईआईटीवाई ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और नए और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को अपनाने की क्षमता बनाने के लिए राष्ट्रीय हित के विभिन्न क्षेत्रों में 42 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की परिकल्पना की है और उन्हें संचालित किया है। ये डोमेन विशिष्ट सीओई इनोवेशन के लोकतंत्रीकरण और प्रोटोटाइप के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों में इनोवेशन केंद्र बनाने में सहायक के रूप में कार्य करते हैं।

v. **थीम आधारित इन्क्यूबेशन केंद्र:** इनोवेशन आधारित **इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और डिजाइन विनिर्माण, एन्टरप्रेन्योर पार्क** लाने के लिए एसटीपीआई नई दिल्ली, कोचीन केरल में मेकर्स विलेज, आईआईआईटी पटना और बिहार सरकार के माध्यम से मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी हैदराबाद में फैबलेस चिप डिजाइन इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है।

सरकार ने पिछले पांच वर्षों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्टार्टअप सहायता योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 10,000 से अधिक तकनीकी स्टार्टअप को सहायता प्रदान की है जिसमें इनक्यूबेटरों के माध्यम से स्टार्टअप्स को लगभग 580 करोड़ रुपये की कुल धनराशि वितरित की गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा समर्थित 3600 से अधिक तकनीकी स्टार्टअप शामिल हैं जिन्हें कुल 212 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा समर्थित तकनीकी स्टार्टअप का योजना-वार ब्यौरा और स्टार्टअप को वितरित की गई धनराशि **अनुबंध-I** में संलग्न है।

****

अनुबंध-I

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त पोषण सहायता के साथ समर्थित तकनीकी स्टार्टअप्स का योजना-वार ब्यौरा

क्र. संख्या	**मंत्रालय/विभाग**	**योजना/कार्यक्रम**	**समर्थित तकनीकी स्टार्टअप की संख्या**	**वितरित धनराशि (करोड़ रुपए में)**
1.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन एवं उद्यमियों का विकास (टाइड 2.0)	1,235	125.0
		उत्पाद इनोवेशन, विकास और वृद्धि के लिए एमईआईटीवाई का स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर कार्यक्रम (समृद्ध)	175	37.6
		नेक्स्ट जेनरेशन इनक्यूबेशन योजना (एनजीआईएस)	530	23.5
		थीम आधारित इन्क्यूबेशन केंद्र	398	4.0
		डोमेन विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)	1,205	7.3
		डिजिटल इंडिया भाषिणी	50	2.5
		चिप्स टू स्टार्ट-अप (सी2एस) कार्यक्रम	10	5.2
		डिजाइन लिंक्ड इन्सेंटिव (डीएलआई) योजना	35	7.3
2.	नीति आयोग	अटल इनोवेशन मिशन	4,106	18.0
3.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)	निधि-सीड सहायता कार्यक्रम	490	154.0
4.	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)	स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) योजना	1,777	195.8
		कुल	**10,011**	**580.2**

****